प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

05.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज ऊना के कोटला कलां स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर समिति द्वारा आयोजित वार्षिक धार्मिक महासम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत गीता में कर्म करने का जो संदेश दिया गया है, उसी कर्मयोग की भावना से प्रदेश सरकार जनकल्याण के कार्यों में निरंतर जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं, आम लोगों और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए संवेदनशील, समावेशी व मानवीय दृष्टिकोण के साथ योजनाओं को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार निराश्रित बच्चों के लिए माता–पिता की भूमिका निभा रही है।

मुकेश अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के भव्य भवन निर्माण, परिसर के सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए पहले चरण में लगभग एक सौ 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें 75 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि शेष राशि स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से प्राप्त हुई है। मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला के अंब उपमंडल के दिलवां में आज एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि श्री चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल योजनाओं पर करीब सवा सौ करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 'हर घर, हर खेत पानी' के लक्ष्य को मिशन मोड में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

धनीराम शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और आधुनिक बना रही है ताकि लोगों को घरद्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके। उन्होने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही।

शांडिल ने कहा कि प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है और करीब एक हजार एक सौ 10 करोड़ रूपए खर्च कर स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत किया गया है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल के लिए राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी बंद होने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 16वें वित्तायोग के सामने राज्य का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। यही कारण था कि केंद्र सरकार ने हिमाचल सहित 17 राज्यों को दी जाने वाली आरडीजी बंद कर दी। उन्होंने दावा किया कि 15वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के बारे में स्पष्ट संकेत दिए थे और हिमाचल की सुक्खू सरकार को सत्ता संभालने के बाद इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए थी लेकिन सरकार अंत तक सोई रही।

नेता प्रतिपक्ष ने वर्ष 2026—27 के केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत का आभार स्तंभ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कर हस्तातंरण के रूप में 13 हजार 9 सौ 49 करोड़ और अनुदान सहायता के तहत दस हजार दो सौ 43 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

बोर्ड परीक्षा

राज्य में आगामी 3 मार्च से आरंभ होने वाली प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में इस बार करीब एक लाख 84 हजार विद्यार्थी भाग लेंगे। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि वार्षिक परीक्षाओं से पहले 20 से 28 फरवरी तक प्रेक्टिकल परीक्षाओं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए बोर्ड की ओर से 2 हजार 3 सौ 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विशाल शर्मा ने बताया कि नकल रोकने के लिए फलाइंग स्क्वायड बनाए जाएंगे और साथ ही लाईव मॉनिटरिंग सैंटर भी स्थापित किया जाएगा।

हमने 2384 जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए हैं पूरे प्रदेश भर में, नकल रोकने के लिए जैसे हर बार हम फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाते हैं वो फ्लाइंग स्कोट्स लगेंगे और एक हम लाइफ मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो बोर्ड के स्तर पर बनाएंगे। इस बार थोड़ा सा हम इसको बड़े स्तर पे करेंगे पहले के मुकाबले। हमारे 100: जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं वहां पे सीसीटीवी कैमरा कंपलसरी है बिल्कुल ।

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————